Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 17-03-2006
Participants : Bangaru Smt. Susheela Laxman

an>

Title : Need to implement National Rural Employment Guarantee Programme in Jalaur Parliamentary Constituency and other parts of Rajasthan.

श्रीमती सुशीला बंगारु लक्ष्मण (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गृह राज्य राजस्थान एवं मेरे संसदीय क्षेत्र जालौर के दलित वर्ग एवं जनजातीय समुदायों में व्याप्त घोर गरीबी, अशिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की ओर इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहती हूं। आजादी के पांच दशक बीत जाने के पश्चात भी राजस्थान के दलितों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनमें ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जनजातीय समुदायों का और बुरा हाल है। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **राजस्थान में सहरिया के सुविधा प्राप्त आदिवासी समुहों में स्वास्थ्य एवं कुपोाण अध्ययन** नामक एक सर्वे प्रायोजित किया था। सर्वे से पता चला कि 80 प्रतिशत से अधिक सहरिया लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनमें कुपो-ाण एवं बीमारी की दर काफी ऊंची है। यही हाल दलितों, पिछड़ों एवं अन्य जनजातीय समुदायों की है। इन समुदायों में कुपोाण को दूर करने के लिए इनकी माली हालत सुधारनी होगी।

अतः मैं मांग करती हूं कि राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को सारे राजस्थान में तुरंत लागू किया जाये। समस्त राजस्थान मलेरिया की चपेट में रहता है। अतः प्रदेश में वृहद मलेरिया नियंत्रण परियोजना को लागू किया जाये। दलित एवं आदिवासी लोग पिछड़े एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं। अतः उन्हें इलाज उपलब्ध कराने के लिए चल औाधालयों से दवा एवं इलाज का प्रबंध किया जाये तथा ऑयरन एवं विटामिन के कैप्सूल बच्चों एवं महिलाओं में अनिवार्य रूप से बांटे जायें तथा इन समुदायों की कल्याण योजनाओं को चलाने के लिए राजस्थान सरकार भरपूर केन्द्रीय ग्रान्टस दे ताकि दलितों एवं आदिवासियों को आवश्यक राहत मिल सके।